



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 अगस्त, 2000/30 श्रावण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 अगस्त, 2000

संख्या 1-55/2000-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का

विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 21 अगस्त, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर संक्षिप्त नाम । (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

1966 का 14      2. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके धारा 4 का पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में,— संशोधन ।

(i) उप-धारा (1) का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रत्येक व्योहारी जो, धारा 7 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल में अन्य रूप से व्यवहार नहीं करता है, वह इस अधिनियम के अधीन उस तागीख से जिस पर, किसी भी वर्ष के दौरान उसके सकल आवर्त कराधेय की मात्रा प्रथमतः अधिक होती है, कर संदत्त करने का दायी होगा ।"

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

धारा 6 का संशोधन ।

(i) उप-धारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु अनुसूची—'क' में यथा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर कर, एक रुपए में बीस पैसे से अनधिक ऐसी दर से, जैसी इस प्रकार अधि-सूचित की जाए, उद्गृहीत किया जा सकेगा, सिवाय—

(क) चूना पत्थर जिस पर एक रुपए में सौ पैसे से अनधिक की दर पर कर ; और

(ख) मद्य (देसी मद्य, विदेशी मद्य और भारत में बनी विदेशी मद्य जिसके अन्तर्गत बीयर है किन्तु भारत में बनी साईडर तथा शराब इसके अन्तर्गत नहीं है), पोलीथीन बैगज और इमारती लकड़ी (किन्तु रूपान्तरित इमारती लकड़ी इसके अन्तर्गत नहीं है) जिन पर एक रुपए में तीस पैसे से अनधिक की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय का तीस दिन से अन्यून का नोटिस देने के पश्चात् ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची "क" में किसी माल को जोड़ या उससे लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी : "; और

(ii) उप-धारा (3) के खण्ड (क) में, उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा।

धारा 7 का  
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (2) में, "अनुसूची—“ख” में जोड़ सकेगी या उस में से लोप कर सकेगी” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, “किसी माल को अनुसूची “—ख” में जोड़ सकेगी या उस में से लोप कर सकेगी या अन्यथा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी”, शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 8 का  
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उप-धाराएं (2), (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(2) हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए माल के उत्पादन के प्रयोजन के लिए कारबार स्थापित करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, के होते हुए भी उसे ऐसी शर्तों के अध्वधीन और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सकेगा, और ऐसा व्यक्ति, जब उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो, जब तक कि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदत्त रहता है। इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण का ऐसा प्रमाण-पत्र शर्तों के अध्वधीन प्रदान किया जाएगा कि, यदि ऐसा व्यक्ति प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारबार स्थापित करने में असफल रहता है या उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो वह निर्धारण अधिकारी के आदेश द्वारा कर की रकम के आधे के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो उसके द्वारा समस्त माल के क्रय करने पर संदत्त की जाती मानो कि वह इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं होता।

(3) उप-धारा (1) द्वारा प्रत्येक व्यौहारी जो रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है और प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है, वह इस निमित्त विहित रीति में निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किया गया आवेदन सही है, वह ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन जैसी विहित की जाए, आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे विहित रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(5) जब कोई व्योहारी इम धारा की उप-धारा (1) के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल हो जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्योहारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रभावी होगा जैसे यह व्योहारी के आवेदन पर उप-धारा (4) के अधीन जारी किया जाता ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा—

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन कर सकेगा—

(क) व्योहारी के आवेदन पर, यदि व्योहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि यह सूचना देता है कि,—

(i) उसने अपना कारबार स्थानांतरित कर लिया है, या

(ii) उसने अपने कारबार का नाम (स्थापना) या स्वरूप बदल लिया है, या

(iii) कारबार नए स्थान पर खोलना चाहता है या कारबार के स्थान में अथवा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट पुन. विक्रय हेतु माल या विक्रय हेतु माल विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले माल के वर्ग या वर्गों में परिवर्तन करना चाहता है ;

(ख) यदि व्योहारी या व्यक्ति ने, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण किया है, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को कार्यान्वित करता है ;

(ग) यथास्थिति, व्योहारी उसके विधिक प्रतिनिधि के आवेदन पर अथवा स्व-प्रेरणा से, ऐसे रद्दकरण तक के संदाय के दायित्व को प्रभावित किए बिना, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा,—

(i) यदि व्योहारी अपना कारबार या कारबार के किसी स्थान का विक्रय करता है या उसे अन्यथा व्ययनित करता है या अपना कारबार जारी नहीं रखता है, या

(ii) यदि व्योहारी की मृत्यु हो जाती है, या

(iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग सहित किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए या इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व की समाप्ति हो जाती है :

परन्तु इस उप-धारा के खण्डों (ख) और (ग) के अधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश नहीं किया किया जाएगा ; और

(घ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण कर सकेगा ।”

धाराएं 8-क,  
9, 10, 10-  
क, 10-ख,  
और 10-ग  
का लोप।

6. मूल अधिनियम की धाराएं 8-क, 9, 10, 10-क, 10-ख और 10-ग का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का  
संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) में,—

(i) “भारतीय रिजर्व बैंक” शब्दों के स्थान पर, “अनुसूचित बैंक जो खजाना बैंक है” शब्द रखे जाएंगे, और

(ii) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि जब व्यौहारी खजाना बैंक से भिन्न अनुसूचित बैंक द्वारा संदाय करता है, वह ऐसे बैंक से, इस प्रभाव का, जैसा विहित किया जाए, एक प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा, कि बैंक ने व्यौहारी के निदेशों पर कर की रकम खजाना बैंक को भेज दी है और निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, उस तारीख की पश्चात्पूर्व तारीख को जिसको ऐसे बैंक द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, व्यौहारी द्वारा कर संदत्त किया गया समझा जाएगा।”

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित बैंक जो खजाना बैंक से भिन्न स्थान पर स्थित है, द्वारा संदाय करने की दशा में, व्यौहारी को सम्बद्ध बैंक से विहित प्रमाण-पत्र, जैसा पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन वर्णित है, उप-धारा (3) के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए विहित देय तारीख के अवसान से कम से कम तीन दिन पूर्व, उपाप्त करना आवश्यक होगा और उस दशा में व्यौहारी द्वारा देय तारीख को संदाय किया गया समझा जाएगा।”।

धारा 21 का  
प्रतिस्थापन। अर्थात् :—

8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“21. प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्धारिती को अनुज्ञात करना.—कोई निर्धारिती, व्यौहारी या अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या जिससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, सिवाय जब स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए, इस निम्न लिखित रूप में, विहित रीति में, उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।”

धारा 25 का  
लोप।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा।

धारा 42-ख  
का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 42-ख के खण्ड (क) में, “कच्ची सामग्री” शब्दों के पश्चात् और “के रूप में” शब्दों से पूर्व, “संयंत्र या मशीनरी” चिह्न और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 की धारा 4, कराधान के आपनन से सम्बन्धित है और अधिनियम के अधीन उपबन्धों को सुव्यवस्थित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि उन्हें व्योहारियों के सभी प्रवर्गों के लिए समरूप बनाया जा सके। धारा 6 के अधीन सरकार अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट माल पर 15% तक की दरों को अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है, सिवाय इसके कि जब इसे उच्चतर दरों पर अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विनिश्चय के अनुरूपतः कतिपय माल पर 20% की न्यूनतम दर, भी पुरःस्थापित की गई है इसलिए सरकार को 20% तक कर उद्गृहीत करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, उपबन्ध बनाकर, उपबन्धों को सरल करने का विनिश्चय किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि विद्युत उर्जा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्/कन्द्र सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रम के अनन्य अधिकार क्षेत्र से निजी कम्पनियों के हाथों चला गया है जो, ऐसी परियोजनाओं से सीधे तौर पर सम्बन्धित सिविल और अन्य सहवृद्ध संकर्मों का दायित्व ले रही है। परिणामतः अधिक दृश्य विधान में भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की भूमिका, उत्पादन और वितरण दोनों क्रिया-कलापों में, एक वाणिज्यिक संगठन की है। परिणामतः विद्युत सैक्टर की अनिवार्यतः वाणिज्यिक प्रकृति के समन्वय, जनसाधारण को विद्युत उर्जा का प्रदाय करने वाली किसी कम्पनी, उपक्रम, अभिकरण इत्यादि को ऐसी उर्जा के उत्पादन या वितरण में इसके द्वारा प्रयोग के लिए माल की विक्री को कराधान की परिधि में लाने का विनिश्चय किया गया है। अधिनियम की धारा 6 और 7 के अधीन सरकार अधिनियम से संलग्न अनुसूची "क" और "ख" में या से किसी माल को जोड़ या उसका लोप कर सकती है। उपबन्धों को पूर्ण करने के लिए इन अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने की शक्तियां देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चूंकि धाराएं 8, 8-क, 9, 10, 10-क, 10-ख और 10-ग, आनुसंगिक विषयों से सम्बन्धित धारा 25 में अतिरिक्त उपबन्ध के इलावा, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञापन इत्यादि विभिन्न उपबन्ध अधिनियमित करती है। इसलिए बहुविध उपबन्धों को समाप्त करना और इसके रजिस्ट्रीकरण, संशोधन, निर्वहन, रद्दकरण से सम्बन्धित एकल सरलीकृत उपबन्ध का पुरःस्थापन करना आवश्यक समझा गया है। अधिनियम की धारा 12 (4) के अधीन व्यवहारी या व्योहारियों को सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा में संदेय ड्राफ्ट/रेखांकित चैक के माध्यम से कर इत्यादि संदत्त करने का विकल्प होगा। किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से ऐसे संदाय को सुकुर बनाने के लिए, यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए। अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं में निर्धारित इत्यादि के प्रतिनिधित्व के प्राधिकृत अधिकारियों की अर्हताओं, अवचार, निरर्हताओं इत्यादि के बारे में धारा 21 विस्तृत उपबन्ध करती है। अधिनियम से इन अनावश्यक प्रक्रिया व्यौरों को हटाना और उपबन्धों को सरल बनाना अनिवार्य है। धारा 42-ख के अधीन नियमित रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता को सिर्फ कच्चे माल पैकिंग और प्रसंस्करण माल रियायती दर पर खरीदने की अनुज्ञा है, जबकि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए संयन्त्र और मशीनरी भी रियायती दर पर खरीदे जाने की अनुज्ञा है। तदनुसार, संयन्त्र और मशीनरी में व्यापार में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान उपबन्धों को सुव्यवस्थित किया जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रवीण शर्मा;  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख ..... 2000

### वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 3 छूट के खण्ड का लोप करने और परिणाम स्वरूप ऐसे विक्रयों को कराधान के कार्यक्षेत्र के भीतर लाने का उपबन्ध करता है। ऐसे कराधान से राजकोष में प्रतिवर्ष लगभग दस करोड़ रुपए की आय होनी सम्भाव्य है। विधेयक अधिनियमित होने पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने हेतु शर्तें और रीति, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें, रजिस्ट्रीकरण की फीस और प्ररूप, अवधि, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण की रीति और इसके लिए संदेय फीस की रकम विहित करने के लिए सशक्त करता है। खण्ड 8 सरकार को, किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि को अधिनियम के अधीन विधिक कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करने की रीति से सम्बन्धित नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य और आवश्यक स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें  
(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्या.....)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान मन्त्रालय में पुरस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

Bill No. 17 of 2000.

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2000**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Second Amendment) Act, 2000.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter called the 'principal Act'),—

(i) sub-section (1) shall be omitted; and

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every dealer who does not deal exclusively in goods declared to be tax free under section 7 shall be liable to pay tax under this Act from the date on which his gross turnover during any year first exceeds the taxable quantum.”.

3. In section 6 of the principal Act,—

Amendment of section 6.

(i) in sub-section (1), for the first proviso the following shall be substituted, namely:—

“Provided that a tax at such rate not exceeding 20 paise in a rupee, as may be so notified, may be levied on the sale of goods as specified in Schedule-‘A’ except on—

(a) Lime-stone on which a tax at the rate not exceeding 100 paise in a rupee, and

(b) Liquor (Country Liquor, Foreign Liquor and Indian Made Foreign Liquor including Bear but excluding Indian made cider and wines), Polythene Bags and Timber (but not including converted timber) on which a tax at the rate not exceeding 30 paise in a rupee,

shall be levied:

Provided further that the Government, after giving by notification not less than thirty days notice of its intention so to do, may, by like notification, add to or delete from Schedule-‘A’ any goods, or otherwise amend the Schedule, and thereupon

the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly;" and

(ii) in sub-section (3), in clause (a), sub-clause (iii) shall be omitted.

Amendment  
of section 7.

4. In section 7 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "add to or delete from Schedule 'B'", the words and signs "add to or delete from Schedule 'B' any goods or otherwise amend the Schedule," shall be substituted.

Amendment  
of section 8.

5. In section 8 of the principal Act, for sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Any person intending to establish a business in Himachal Pradesh for the purpose of manufacturing goods for sale may, notwithstanding that he is not liable to registration under sub-section (1), be granted a registration certificate subject to such conditions and in the manner as may be prescribed, and such person when granted a registration certificate shall, for so long as such certificate is in force, be liable to pay tax under the Act :

Provided that grant of such a certificate of registration shall be subject to the conditions that if such person fails to establish the business within the period specified in the certificate or fails to comply with any of the conditions specified therein, he shall be liable by order of the Assessing Authority, to pay a penalty equivalent to one-half of the amount of tax which would have been payable by him in respect of all the goods purchased by him as if he had not been registered under this sub-section.

(3) Every dealer required by sub-section (1) to be registered and every person who may be granted registration certificate under sub-section (2) shall make application in this behalf in the prescribed manner to the Assessing Authority.

(4) If the Assessing Authority is satisfied that an application for registration made under sub-section (3) is in order, he shall, in accordance with such rules and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed form.

(5) When any dealer fails to apply for registration in contravention of sub-section (1) of this section, the Assessing Authority shall register such dealer and grant him a certificate of registration and such registration shall take effect as if it had been made under sub-section (4) of this section on the dealer's application.

(6) The Assessing Authority may, by order,—

(a) amend certificate of registration on the dealer's application if the dealer or his legal representative furnishes the information that he—

(i) has transferred his business, or

- (ii) has changed the name (constitution) or nature of his business, or
- (iii) wants to open a new place of business or make any change either in the places of business or in the class or classes of goods specified in his certificate of registration for resale or for use in manufacture of goods for sale ;
- (b) suspend a certificate of registration, without prejudice to any other penalty, if the dealer or person has violated any provision of this Act or rules made thereunder ;
- (c) cancel a certificate of registration, on dealer's or, as the case may be, of his legal representative's application or *suo-moto*, without affecting liability to pay tax till such cancellation,—
  - (i) if the dealer sells or otherwise disposes of his business or any place of business or discontinues his business, or
  - (ii) if the dealer dies, or
  - (iii) for any other sufficient cause including misuse of the certificate of registration or cessation of liability to payment of tax under this Act;

Provided that no order affecting any person adversely shall be made under clauses (b) and (c) of this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard ; and

- (d) renew a certificate of registration for such period and in the manner and on payment of such fee as may be prescribed.”.

6. Sections 8-A, 9, 10, 10-A, 10-B and 10-C of the principal Act shall be omitted.

Omission of sections 8-A, 9, 10, 10-A, 10-B and 10-C.

7. In section 12 of the principal Act, in sub-section (4),—

Amendment of section 12.

- (i) for the words “Reserve Bank of India”, the words “Scheduled Bank which is a treasury bank” shall be substituted, and
- (ii) after the first proviso, the following provisos shall be added, namely:—

“Provided further that when a dealer makes payment through a Scheduled Bank other than the treasury bank, he shall obtain from such bank a certificate, as may be prescribed, to the effect that the bank has remitted the amount of tax to the treasury bank on the dealer's directions and on production of such certificate to the Assessing Authority the dealer shall be deemed to have paid the tax on the date following the date on which such certificate is issued by such bank:

Provided further that in case of payment through a Scheduled Bank which is located at a station other than that of the treasury bank, the dealer shall need to procure the prescribed certificate from the concerned bank, as mentioned under the preceding proviso, at least three days before the expiry of the due date

prescribed under sub-section (3) for filing the return and in that case the dealer shall be deemed to have made the payment by due date."

**Substitution of section-21.** 8. For section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"21. *Assesses etc. permitted to attend through authorized agent.*—

Any assessee, dealer or other person, who is entitled or required to attend before any authority in connection with any proceedings under this Act, except when required to attend in person, may attend through a person authorized by him in writing in this behalf, in the prescribed manner."

**Omission of section 25.** 9. Section 25 of the principal Act shall be omitted.

**Amendment of section 42-B.** 10. In section 42-B of the principal Act, in clause (a), after the words "raw material" but before the words "in the manufacture", the sign and words ", plant or machinery" shall be inserted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, deals with the incidence of taxation and it has been decided to rationalize the provisions under the Act so as to make them similar for all categories of dealers. Under section 6 the Government is authorized to notify the rates of tax on goods specified in Schedule-'A' upto 15% except when otherwise specified at higher rates. Since in conformity with the decision at the national level, a floor rate of 20% on certain goods has also been introduced, it has been decided to simplify the provision by making a provision enabling the Government to levy tax upto 20%. Besides, the generation of electric energy has since passed from the exclusive domain of the Himachal Pradesh State Electricity Board/Central Government Public Sector Undertaking to that of private companies, which are undertaking civil and other related works directly connected with such projects. Also in the changed economic scenario the role of the Himachal Pradesh State Electricity Board is that of a commercial organization, in both generation and distribution activities. Consequently, consistent with essentially commercial nature of electricity sector, it has been decided to bring sales, made to any company, undertaking, agency etc. supplying electrical energy to the public, of goods for use by it in the generation or distribution of such energy, within the ambit of taxation. Under sections 6 and 7 of the Act, the Government can only add to or delete any goods from Schedule-'A' and Schedule-'B' appended to the Act. In order to make the provisions complete it is essential to give enabling powers to the Government to amend these Schedules. Further, since sections 8, 8-A, 9, 10, 10-A, 10-B and 10-C enact different provisions for registration, licensing etc. under the Act besides additional provision in section 25 relating to ancillary matters, it is considered necessary to do away with multiple provisions and introduce a single simplified provision relating to registration, amendment, suspension, cancellation and renewal thereof. Under section 12 (4) of the Act, the dealers have option either to make payment of tax etc. into the government treasury or Reserve Bank of India or through a draft/crossed cheque payable by local branch of the Scheduled Bank. In order to facilitate such payments through any Scheduled Bank, it has also been decided to suitably amend the Act. Section 21 makes detailed provisions about qualifications, misconduct, disqualifications etc. of agents authorized to represent the assessee etc. in proceedings under the Act. It is essential to remove these unnecessary procedural details from the Act and to simplify the provisions. Under section 42-B, a regularly registered manufacturer is allowed to purchase only raw material, packing and processing material at concessional rate while under the Central Sales Tax Act, 1956, even plant and machinery are allowed to be purchased at concessional rate for use in manufacture of goods. Accordingly, in order to encourage investment in trading in plant and machinery, it has been decided to rationalize existing provisions.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**PRAVEEN SHARMA,**  
Minister-in-Charge.

SHIMLA  
Dated . . . . ., 2000.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill provides for omission of exemption clause from the Act and consequently to bring such sales within the purview of taxation. Such taxation is likely to yield about Rs. 10 crores annually to the State exchequer. The provisions of the Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and will not result in additional expenditure from the State exchequer.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill empowers the Government to prescribe conditions and manner of grant of a registration certificate, manner of making application for registration, conditions of registration, fee and form of certificate of registration, period, manner of renewal of certificate of registration and amount of fee payable therefor. Clause 8 empowers the Government to make rules relating to the manner of authorizing an agent or a representative for attendance at legal proceedings under the Act. These delegations of powers are normal and essential in character.

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Excise and Taxation Department File No. EXN-F(II)-12/2000].

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 2000, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.